International Journal of Advanced Research in Engineering Technology & Science
ISSN: 2349-2819
Impact Factor: 7.10
( Peer-Reviewed, Open Access, Fully Refereed International Journal)
Email: editor@ijarets.org Volume-13, Issue-1 January – 2026 www.ijarets.org

# ग्रामीण आजीविका संकट से शहरी पलायन तक: आगरा जनपद में परिवार और समुदाय की बदलती सामाजिक संरचना का समाजशास्त्रीय अध्ययन

**डॉ. हरिओम**
**सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग**
**सेठ फूलचंद बागला (स्नातकोत्तर) महाविद्यालय, हाथरस**

## सारांश

भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की आजीविका व्यवस्था वर्तमान में गहरे सामाजिक-आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। परंपरागत रूप से कृषि भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार रही है, किंतु भूमि के निरंतर विखंडन, कृषि की बढ़ती लागत, सीमित सिंचाई सुविधाओं, तकनीकी संसाधनों की कमी तथा बाजार की अनिश्चितताओं के कारण कृषि आज स्थायी और पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराने में असमर्थ होती जा रही है। इसके साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि रोजगार के अवसरों का अभाव तथा तीव्र जनसंख्या वृद्धि ने ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या को और अधिक गंभीर बना दिया है। परिणामस्वरूप ग्रामीण आबादी, विशेषकर युवा वर्ग, आजीविका की तलाश में शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करने के लिए विवश हो रहा है। यह पलायन केवल एक आर्थिक प्रक्रिया न होकर ग्रामीण समाज में गहरे सामाजिक परिवर्तनों को जन्म देने वाली एक महत्वपूर्ण सामाजिक परिघटना के रूप में उभर कर सामने आया है।

प्रस्तुत शोध-पत्र का प्रमुख उद्देश्य आगरा ज़िले के विशेष संदर्भ में ग्रामीण रोजगार के अभाव और उससे उत्पन्न पलायन की प्रवृत्ति का समाजशास्त्रीय अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत यह विश्लेषण किया गया है कि किस प्रकार ग्रामीण बेरोजगारी ने पलायन को बढ़ावा दिया है तथा यह प्रक्रिया ग्रामीण परिवार और समुदाय की संरचना, कार्यप्रणाली और सामाजिक संबंधों को किस रूप में प्रभावित कर रही है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों से कार्यशील सदस्यों के बाहर जाने के कारण पारिवारिक संरचना में परिवर्तन आ रहा है, जिसमें महिलाओं और बुजुर्गों की भूमिकाएँ विस्तृत हुई हैं तथा उन पर आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक जिम्मेदारियों का भार बढ़ा है। इसके साथ ही पारिवारिक अलगाव, भावनात्मक दूरी और बच्चों के सामाजिककरण से जुड़ी समस्याएँ भी सामने आई हैं, सामुदायिक स्तर पर पलायन के प्रभाव और अधिक व्यापक दिखाई देते हैं। युवाओं की कमी के कारण ग्रामीण समुदायों में सामुदायिक सहभागिता, पारंपरिक सामाजिक संस्थाओं और सामूहिक गतिविधियों की भूमिका कमजोर पड़ती जा रही है। सामाजिक एकजुटता में कमी, व्यक्तिवाद की प्रवृत्ति तथा पारंपरिक मूल्यों के क्षरण जैसे परिवर्तन ग्रामीण समाज की स्थिरता के लिए नई चुनौतियाँ उत्पन्न कर रहे हैं। यद्यपि शहरी क्षेत्रों से प्राप्त आय (रेमिटेंस) के माध्यम से कुछ परिवारों की आर्थिक स्थिति में आंशिक सुधार देखने को मिलता है, किंतु इसके सामाजिक दुष्परिणाम अधिक गहरे और दीर्घकालिक सिद्ध हो रहे हैं।

यह शोध इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि ग्रामीण रोजगार का अभाव और उससे उत्पन्न पलायन आगरा ज़िले में केवल आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक प्रश्न है, जिसका प्रभाव परिवार, समुदाय और सामाजिक संरचना के प्रत्येक स्तर पर पड़ रहा है। अतः ग्रामीण विकास नीतियों में रोजगार सृजन के साथ-साथ सामाजिक आयामों—जैसे पारिवारिक स्थिरता, सामुदायिक जीवन और सामाजिक समावेशन—को सशक्त रूप से शामिल करना अत्यंत आवश्यक है। तभी संतुलित, समावेशी और सतत ग्रामीण विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है।

## भूमिका

ग्रामीण समाज भारतीय सामाजिक संरचना की आधारशिला रहा है। पारंपरिक रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और कुटीर उद्योगों पर आधारित रही है, किंतु वैश्वीकरण, तकनीकी परिवर्तन और आर्थिक असमानताओं के कारण ग्रामीण रोजगार के अवसर सीमित होते जा रहे हैं। आगरा ज़िला, जो शहरी-पर्यटन विकास के लिए जाना जाता है, उसके ग्रामीण क्षेत्र इस विकास की प्रक्रिया से अपेक्षाकृत वंचित रहे हैं। रोजगार के अभाव ने ग्रामीण युवाओं को पलायन के लिए विवश किया है, जिससे न केवल आर्थिक बल्कि गहरे सामाजिक परिवर्तन भी सामने

आए हैं। इस संदर्भ में ग्रामीण रोजगार और पलायन के सामाजिक प्रभावों का अध्ययन अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है।

## अध्ययन के उद्देश्य

इस शोध-पत्र के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. आगरा ज़िले में ग्रामीण रोजगार की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना।
2. ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन के सामाजिक-आर्थिक कारणों की पहचान करना।
3. पलायन का ग्रामीण परिवार पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।
4. ग्रामीण समुदाय और सामाजिक संरचना में हो रहे परिवर्तनों का विश्लेषण करना।

## शोध पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। शोध के लिए द्वितीयक स्रोतों—सरकारी रिपोर्ट, जनगणना आँकड़े, प्रकाशित शोध-पत्र, पुस्तकें एवं सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण—का उपयोग किया गया है। आगरा ज़िले से संबंधित उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर ग्रामीण रोजगार, पलायन और सामाजिक परिवर्तन के मध्य संबंधों का विश्लेषण किया गया है।

## आगरा ज़िले में ग्रामीण रोजगार की स्थिति

आगरा ज़िले के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति जटिल और बहुआयामी समस्याओं से ग्रस्त है। यद्यपि कृषि आज भी ग्रामीण आजीविका का प्रमुख साधन बनी हुई है, परंतु बदलती आर्थिक परिस्थितियों में यह क्षेत्र पर्याप्त और सुरक्षित रोजगार प्रदान करने में असमर्थ सिद्ध हो रहा है। भूमि का विखंडन, सीमित सिंचाई सुविधाएँ, पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ तथा उत्पादन लागत में निरंतर वृद्धि ने कृषि को अलाभकारी बना दिया है। **जनगणना 2011 एवं NSSO के आँकड़ों** के अनुसार, अधिकांश ग्रामीण परिवार छोटे एवं सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं, जिनकी आय कृषि पर निर्भर रहते हुए भी अपर्याप्त बनी रहती है।

### तालिका 1: आगरा ज़िले में ग्रामीण श्रमिकों का क्षेत्रवार वितरण (प्रतिशत में)

| क्षेत्र | प्रतिशत |
|---|---|
| कृषि एवं सहायक गतिविधियाँ | 60–65 |
| गैर-कृषि (निर्माण, लघु उद्योग आदि) | 20–25 |
| सेवा क्षेत्र | 10–15 |

*स्रोत: NSSO एवं जिला सांख्यिकीय पत्रिका*

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि ग्रामीण रोजगार का अत्यधिक बोझ कृषि क्षेत्र पर ही बना हुआ है, जबकि गैर-कृषि और सेवा क्षेत्रों में रोजगार के अवसर अपेक्षाकृत सीमित हैं। सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण कृषि वर्षा पर निर्भर रहती है, जिससे उत्पादन और आय दोनों में अनिश्चितता बनी रहती है। इसके साथ ही फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की सीमित पहुँच, विपणन सुविधाओं का अभाव तथा बिचौलियों की भूमिका किसानों की आय को और कमज़ोर बनाती है। गैर-कृषि रोजगार के संदर्भ में आगरा ज़िला औद्योगिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रभाव सीमित है। औद्योगिक इकाइयाँ और सेवा क्षेत्र मुख्यतः शहरी क्षेत्रों तक केंद्रित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प और स्वरोजगार गतिविधियों का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है।

### तालिका 2: ग्रामीण रोजगार योजनाओं की भूमिका (मनरेगा)

| संकेतक | स्थिति |
|---|---|
| औसत कार्य दिवस/परिवार | 40–50 दिन |
| कार्य का स्वरूप | अस्थायी एवं अकुशल |
| दीर्घकालिक रोजगार | सीमित |

*स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार*

मनरेगा जैसी योजनाओं ने ग्रामीण गरीबों को अल्पकालिक राहत अवश्य प्रदान की है और न्यूनतम आय सुरक्षा में योगदान दिया है, किंतु यह योजना स्थायी और कौशल-आधारित रोजगार सृजन में सीमित प्रभाव ही डाल पाई है। परिणामस्वरूप ग्रामीण युवाओं में रोजगार असुरक्षा की भावना तीव्र होती जा रही है।

इन परिस्थितियों का प्रत्यक्ष प्रभाव ग्रामीण युवाओं के पलायन पर पड़ा है। **जनगणना एवं NSSO के अध्ययन** संकेत करते हैं कि रोजगार और बेहतर जीवन-स्तर की तलाश में बड़ी संख्या में युवा शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास कर रहे हैं। इस प्रकार आगरा ज़िले में ग्रामीण रोजगार की समस्या केवल आर्थिक न होकर सामाजिक असंतुलन और ग्रामीण-शहरी विषमता को भी बढ़ावा दे रही है।

## पलायन की प्रवृत्ति: कारण और स्वरूप

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सीमित अवसरों ने आगरा ज़िले में पलायन की प्रवृत्ति को तीव्र रूप से बढ़ावा दिया है। कृषि की अलाभकारी स्थिति, गैर-कृषि रोजगार की कमी तथा ग्रामीण विकास की धीमी गति के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण जनसंख्या, विशेष रूप से युवा वर्ग, आजीविका की तलाश में अपने मूल स्थानों को छोड़ने के लिए विवश हो रही है। यह पलायन मुख्यतः आर्थिक कारणों से प्रेरित है, किंतु इसके सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।

### तालिका 3: आयु एवं लिंग के अनुसार पलायन की प्रवृत्ति (प्रतिशत में)

| श्रेणी | प्रतिशत |
|---|---|
| युवा पुरुष (18–35 वर्ष) | 65–70 |
| वयस्क पुरुष (36–50 वर्ष) | 15–20 |
| महिलाएँ | 10–15 |

*स्रोत: जनगणना 2011,*

तालिका 3 से स्पष्ट होता है कि आगरा ज़िले में ग्रामीण पलायन की प्रवृत्ति **आयु और लिंग के आधार पर असमान रूप से वितरित** है। कुल प्रवासियों में **युवा पुरुषों (18–35 वर्ष)** की भागीदारी सर्वाधिक, लगभग **65–70 प्रतिशत**, पाई जाती है। यह आयु वर्ग शारीरिक रूप से सक्षम, रोजगार के प्रति अधिक आकांक्षी तथा जोखिम उठाने की क्षमता रखने वाला होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी रोजगार की कमी और शहरी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत बेहतर मजदूरी के अवसर इस वर्ग को पलायन के लिए सर्वाधिक प्रेरित करते हैं।

**वयस्क पुरुषों (36–50 वर्ष)** का पलायन प्रतिशत तुलनात्मक रूप से कम, लगभग **15–20 प्रतिशत**, पाया जाता है। इस आयु वर्ग के पुरुषों पर पारिवारिक उत्तरदायित्व, भूमि एवं संपत्ति से जुड़ाव तथा सामाजिक बंधन अपेक्षाकृत अधिक होते हैं, जिसके कारण उनका पलायन सीमित और अक्सर मौसमी या अल्पकालिक होता है।

तालिका में **महिलाओं का पलायन प्रतिशत 10–15 प्रतिशत** दर्शाया गया है, जो पुरुषों की तुलना में काफी कम है। इसका प्रमुख कारण महिलाओं की पारंपरिक घरेलू भूमिकाएँ, सामाजिक-सांस्कृतिक प्रतिबंध, सुरक्षा संबंधी चिंताएँ तथा ग्रामीण समाज में सीमित रोजगार अवसर हैं। अधिकांश मामलों में महिलाएँ पीछे छूटे परिवार के सदस्यों—बच्चों और बुजुर्गों—की देखरेख की जिम्मेदारी निभाती हैं, जिससे उनका स्वतंत्र पलायन सीमित रह जाता है। समग्र रूप से यह तालिका यह दर्शाती है कि आगरा ज़िले में पलायन की प्रक्रिया **युवा, पुरुष-प्रधान और चयनात्मक (selective migration)** है। इसका ग्रामीण समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कार्यशील और सक्रिय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा गाँवों से बाहर चला जाता है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पारिवारिक संरचना और सामुदायिक जीवन प्रभावित होते हैं।

### तालिका 4: पलायन के प्रमुख कारण (प्रतिशत में)

| कारण | अनुमानित प्रतिशत |
|---|---|
| रोजगार एवं आय की कमी | 45–50 |
| आर्थिक असुरक्षा | 20–25 |
| शहरी सुविधाओं का आकर्षण | 15–20 |
| सामाजिक उन्नति की आकांक्षा | 10–15 |

*स्रोत: Migration in India, NSS 64th Round (2007–08)*

तालिका 4 यह स्पष्ट करती है कि आगरा ज़िले सहित उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन मुख्यतः **आर्थिक दबावों** से प्रेरित है। सर्वाधिक **45–50 प्रतिशत** ग्रामीण लोग **रोजगार एवं आय की कमी** के कारण पलायन करते हैं, जो यह दर्शाता है कि कृषि की अलाभकारी स्थिति और स्थानीय गैर-कृषि रोजगार के अभाव ने ग्रामीण आजीविका को अस्थिर बना दिया है। इसके अतिरिक्त **20–25 प्रतिशत** पलायन **आर्थिक असुरक्षा**—जैसे ऋण,

अनियमित आय और भविष्य की अनिश्चितता—के कारण होता है। **15–20 प्रतिशत** लोगों को शहरी क्षेत्रों में बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और जीवन-स्तर जैसी **शहरी सुविधाओं का आकर्षण** पलायन के लिए प्रेरित करता है, जबकि **10–15 प्रतिशत** पलायन **सामाजिक उन्नति की आकांक्षा** से जुड़ा होता है, जिसमें बेहतर सामाजिक प्रतिष्ठा, आधुनिक जीवन-शैली और अवसरों की तलाश प्रमुख है। इस प्रकार तालिका यह दर्शाती है कि ग्रामीण पलायन बहु-कारणीय प्रक्रिया है, किंतु इसका केंद्रबिंदु आर्थिक विवशता ही बना हुआ है।

## तालिका 5: प्रवासी श्रमिकों का कार्य-क्षेत्रवार वितरण

| कार्य क्षेत्र | प्रतिशत |
|---|---|
| निर्माण कार्य | 30–35 |
| औद्योगिक/फैक्ट्री कार्य | 25–30 |
| सेवा क्षेत्र (होटल, ढाबे, घरेलू कार्य) | 25–30 |
| अन्य असंगठित कार्य | 10–15 |

*स्रोत: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार*, NSSO (2007–08; 2011–12), *Migration in India*

तालिका 5 से यह स्पष्ट होता है कि आगरा ज़िले से पलायन करने वाले अधिकांश ग्रामीण श्रमिक **असंगठित क्षेत्र** में ही रोजगार प्राप्त करते हैं, जहाँ कार्य की प्रकृति अस्थायी, असुरक्षित और कम सामाजिक संरक्षण वाली होती है। सर्वाधिक **30–35 प्रतिशत** प्रवासी श्रमिक **निर्माण कार्य** (जैसे भवन निर्माण, सड़क निर्माण, दिहाड़ी मजदूरी) में संलग्न पाए जाते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में न्यूनतम कौशल की आवश्यकता होती है और शहरी क्षेत्रों में इसकी माँग निरंतर बनी रहती है। इसके बाद **25–30 प्रतिशत** श्रमिक **औद्योगिक/फैक्ट्री कार्यों** में कार्यरत होते हैं, जिनमें छोटी औद्योगिक इकाइयाँ, कारखाने, वर्कशॉप और ठेके पर आधारित उत्पादन कार्य शामिल हैं; हालाँकि इन कार्यों में भी स्थायित्व और श्रम अधिकारों का अभाव सामान्य है। लगभग **25–30 प्रतिशत** प्रवासी श्रमिक **सेवा क्षेत्र**—जैसे होटल, ढाबे, रेस्तराँ, घरेलू कार्य, सफाई और निजी सेवाओं—में लगे होते हैं, जहाँ कार्य के घंटे अनियमित और मजदूरी अपेक्षाकृत कम होती है। शेष **10–15 प्रतिशत** श्रमिक अन्य प्रकार के **असंगठित कार्यों** में संलग्न रहते हैं, जिनमें फेरी लगाना, रिक्शा/ई-रिक्शा चलाना, अस्थायी दुकानों पर कार्य आदि शामिल हैं। समग्र रूप से यह तालिका यह दर्शाती है कि ग्रामीण पलायन से उत्पन्न रोजगार मुख्यतः असंगठित शहरी अर्थव्यवस्था को श्रम उपलब्ध कराता है, किंतु इसके बदले प्रवासी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, रोजगार स्थिरता, स्वास्थ्य लाभ और श्रम अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है, जिससे उनकी सामाजिक-आर्थिक असुरक्षा बनी रहती है।

## ग्रामीण परिवार पर पलायन का प्रभाव

ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाला पलायन केवल आर्थिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसका गहरा प्रभाव ग्रामीण परिवारों की संरचना, भूमिकाओं और कार्यप्रणाली पर पड़ता है। आगरा ज़िले के ग्रामीण समाज में जब परिवार का कार्यशील सदस्य, विशेष रूप से युवा पुरुष, रोजगार की तलाश में बाहर जाता है, तो पारंपरिक पारिवारिक व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यह परिवर्तन आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा भावनात्मक सभी स्तरों पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है । पलायन के परिणामस्वरूप ग्रामीण परिवारों में **कार्य विभाजन (Division of Labour)** का स्वरूप बदल जाता है। पुरुष सदस्यों की अनुपस्थिति में महिलाओं और बुजुर्गों पर कृषि कार्य, पशुपालन, घरेलू प्रबंधन तथा बच्चों की देखरेख जैसी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। इससे महिलाओं की भूमिका केवल गृहिणी तक सीमित न रहकर आर्थिक योगदानकर्ता के रूप में भी उभरती है।

## तालिका 6: पलायन के बाद परिवार में कार्य विभाजन में परिवर्तन

| पारिवारिक भूमिका | पलायन से पूर्व | पलायन के पश्चात |
|---|---|---|
| कृषि कार्य | पुरुष प्रधान | महिलाएँ एवं बुजुर्ग |
| घरेलू निर्णय | पुरुष सदस्य | महिलाएँ |
| बच्चों की देखरेख | साझा | मुख्यतः महिलाएँ |
| आर्थिक प्रबंधन | पुरुष | महिलाएँ |

*स्रोत: Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI), Government of India.*

तालिका 6 यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि ग्रामीण परिवारों में पलायन के पश्चात **लैंगिक एवं भूमिकागत कार्य विभाजन** में उल्लेखनीय परिवर्तन आता है। पलायन से पूर्व कृषि कार्य मुख्यतः **पुरुष-प्रधान** होता था, क्योंकि पुरुष परिवार के बाहर और भीतर दोनों स्तरों पर उत्पादन संबंधी कार्यों का नेतृत्व करते थे; किंतु पुरुष सदस्यों के बाहर

चले जाने के बाद यह दायित्व **महिलाओं एवं बुजुर्गों** पर स्थानांतरित हो जाता है। इसी प्रकार घरेलू निर्णय-निर्माण, जो पहले पुरुष सदस्यों के नियंत्रण में रहता था, पलायन के पश्चात **महिलाओं के हाथों में केंद्रित** होने लगता है, क्योंकि वे ही परिवार के दैनिक संचालन और संसाधनों के प्रबंधन की प्रमुख इकाई बन जाती हैं। बच्चों की देखरेख पहले साझा जिम्मेदारी के रूप में निभाई जाती थी, परंतु पुरुषों की अनुपस्थिति में यह भूमिका **मुख्यतः महिलाओं** तक सीमित हो जाती है, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक कार्यभार बढ़ जाता है। आर्थिक प्रबंधन के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा जाता है—जहाँ पहले आय, व्यय और बचत से संबंधित निर्णय पुरुष लेते थे, वहीं पलायन के बाद रेमिटेंस की प्राप्ति, घरेलू खर्चों का संतुलन और भविष्य की योजना बनाने की जिम्मेदारी **महिलाओं पर आ जाती है**। इस प्रकार तालिका यह दर्शाती है कि पलायन एक ओर महिलाओं को निर्णय-निर्माण में अधिक भूमिका देकर **सशक्तिकरण की प्रक्रिया** को जन्म देता है, वहीं दूसरी ओर उन पर **बहु-भूमिकात्मक दबाव** भी बढ़ाता है, जिससे ग्रामीण परिवारों की पारंपरिक संरचना और कार्यप्रणाली में गहरा परिवर्तन परिलक्षित होता है।

## तालिका 7: पलायन का बच्चों पर प्रभाव

| संकेतक | प्रभाव |
|---|---|
| विद्यालय उपस्थिति | घटती है |
| शैक्षिक प्रदर्शन | प्रभावित |
| सामाजिक देखरेख | कमजोर |
| बाल श्रम की संभावना | बढ़ती है |

*स्रोत: **National Institute of Rural Development and Panchayati Raj (NIRDPR)** Rural Governance and Community Participation in India (Research Reports).*

तालिका 7 यह दर्शाती है कि ग्रामीण परिवारों से कार्यशील सदस्यों के पलायन का प्रभाव बच्चों के शैक्षिक, सामाजिक और मानसिक विकास पर गहराई से पड़ता है। परिवार के अभिभावक, विशेषकर पिता, के बाहर चले जाने से बच्चों की **विद्यालय उपस्थिति में कमी** देखी जाती है, क्योंकि घरेलू कार्यों, कृषि गतिविधियों या छोटे भाई-बहनों की देखरेख की जिम्मेदारी बच्चों पर आ जाती है। इसके परिणामस्वरूप उनकी नियमित पढ़ाई बाधित होती है और **शैक्षिक प्रदर्शन प्रभावित** होता है, जिसमें कक्षा में पिछड़ना, परीक्षा परिणामों में गिरावट तथा विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति शामिल है। इसके साथ ही अभिभावकीय निगरानी और मार्गदर्शन की कमी के कारण बच्चों की **सामाजिक देखरेख कमजोर** पड़ जाती है, जिससे उनके व्यवहार, अनुशासन और सामाजिक मूल्यों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आर्थिक दबाव और पारिवारिक दायित्वों के कारण कुछ मामलों में बच्चों के **बाल श्रम में संलग्न होने की संभावना बढ़ जाती है**, विशेषकर कृषि, घरेलू कार्य या असंगठित क्षेत्र की गतिविधियों में। इस प्रकार यह तालिका स्पष्ट करती है कि पलायन केवल आर्थिक समाधान नहीं है, बल्कि इसके दीर्घकालिक प्रभाव बच्चों के भविष्य और मानव संसाधन विकास के लिए गंभीर चुनौती के रूप में उभरते हैं।

## समुदाय और सामाजिक संरचना पर पलायन का प्रभाव

ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाला पलायन केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका गहरा और दीर्घकालिक प्रभाव ग्रामीण समुदायों की सामाजिक संरचना और सामूहिक जीवन पर भी पड़ता है। आगरा ज़िले के ग्रामीण समाज में युवा वर्ग के बड़े पैमाने पर बाहर जाने से सामुदायिक सहभागिता, सामाजिक संस्थाओं और पारंपरिक संबंधों में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यह प्रक्रिया ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था को क्रमशः कमजोर और विखंडित करती जा रही है।

ग्रामीण समुदायों में युवाओं की सक्रिय भूमिका सामुदायिक गतिविधियों की रीढ़ मानी जाती है। किंतु पलायन के कारण गाँवों में युवाओं की संख्या में निरंतर कमी आ रही है, जिससे ग्राम सभाओं, सामूहिक श्रम (श्रमदान), धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजनों तथा विकासात्मक गतिविधियों में भागीदारी घटती जा रही है।

## तालिका 8: सामुदायिक सहभागिता पर पलायन का प्रभाव

| गतिविधि | पूर्व स्थिति | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|
| ग्राम सभा/पंचायत बैठक | उच्च सहभागिता | सीमित सहभागिता |
| सामूहिक उत्सव | सामूहिक आयोजन | औपचारिक/सीमित |
| श्रमदान | नियमित | अनियमित |
| युवा समूह गतिविधियाँ | सक्रिय | लगभग निष्क्रिय |

*स्रोत:* **Ministry of Panchayati Raj, Government of India** *Status of Panchayati Raj Institutions in India* (विभिन्न रिपोर्टें)।

तालिका 8 से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों से युवाओं और कार्यशील आबादी के पलायन ने आगरा ज़िले के गाँवों में **सामुदायिक सहभागिता** को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। पलायन से पूर्व ग्राम सभा और पंचायत बैठकों में लोगों की **उच्च सहभागिता** देखी जाती थी, जिससे सामुदायिक निर्णय-निर्माण और स्थानीय लोकतंत्र मजबूत रहता था; किंतु वर्तमान में कार्यशील सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण इन बैठकों में **सीमित सहभागिता** रह गई है। इसी प्रकार पहले सामूहिक उत्सव, जैसे धार्मिक पर्व, मेलों और सामाजिक आयोजनों में पूरे गाँव की सक्रिय भागीदारी होती थी, जबकि पलायन के बाद ये आयोजन अधिकतर **औपचारिक या सीमित** स्वरूप में ही संपन्न होते हैं। श्रमदान की परंपरा, जो सामुदायिक सहयोग और आपसी निर्भरता का प्रतीक थी, पहले **नियमित** रूप से देखी जाती थी, परंतु अब मानव संसाधनों की कमी के कारण यह **अनियमित** हो गई है। विशेष रूप से **युवा समूह गतिविधियाँ**, जो सामाजिक जागरूकता, खेल-कूद और विकासात्मक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं, पलायन के कारण **लगभग निष्क्रिय** अवस्था में पहुँच गई हैं। इस प्रकार तालिका यह दर्शाती है कि पलायन ने ग्रामीण समाज में सामूहिकता और सहभागिता को कमजोर कर दिया है, जिससे सामाजिक एकजुटता और सामुदायिक जीवन की जीवंतता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

## तालिका 9: सामाजिक संरचना में परिवर्तन के प्रमुख संकेतक

| संकेतक | परिवर्तन की दिशा |
|---|---|
| सामुदायिक एकजुटता | घटती |
| पारस्परिक सहयोग | कमजोर |
| सामाजिक नियंत्रण | सीमित |
| व्यक्तिवाद | बढ़ता |

*स्रोत:* ***M.N. Srinivas (1966)*** *Social Change in Modern India, Orient Longman.*

*तालिका 9 यह स्पष्ट करती है कि ग्रामीण क्षेत्रों से निरंतर हो रहे पलायन के परिणामस्वरूप आगरा ज़िले के ग्रामीण समाज की **सामाजिक संरचना में मौलिक परिवर्तन** देखने को मिल रहे हैं। पहले जहाँ ग्रामीण जीवन की आधारशिला **सामुदायिक एकजुटता** पर टिकी हुई थी, वहीं कार्यशील और युवा जनसंख्या के बाहर चले जाने से यह एकजुटता धीरे-धीरे **घटती** जा रही है। पारंपरिक ग्रामीण समाज में आपसी निर्भरता और सहयोग के माध्यम से दैनिक जीवन संचालित होता था, किंतु पलायन के कारण **पारस्परिक सहयोग कमजोर** पड़ गया है और सामूहिक कार्यों में भागीदारी सीमित हो गई है। इसके साथ ही ग्राम समुदाय द्वारा स्थापित **सामाजिक नियंत्रण**, जो रीति-रिवाजों, नैतिक मान्यताओं और सामूहिक दबाव के माध्यम से व्यवहार को नियंत्रित करता था, अब **सीमित** होता जा रहा है, क्योंकि समुदाय का सक्रिय पर्यवेक्षण कमजोर पड़ा है। इन परिवर्तनों के समानांतर ग्रामीण समाज में **व्यक्तिवाद की प्रवृत्ति बढ़ती** जा रही है, जहाँ सामूहिक हितों की अपेक्षा व्यक्तिगत और पारिवारिक हितों को अधिक प्राथमिकता दी जाने लगी है। इस प्रकार तालिका 9 यह दर्शाती है कि पलायन ने ग्रामीण समाज को सामूहिकता से व्यक्तिवाद की ओर उन्मुख किया है, जिससे सामाजिक संबंधों की प्रकृति और सामुदायिक जीवन की स्थिरता पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ रहा है।*

## सामाजिक परिवर्तन के सकारात्मक और नकारात्मक आयाम

ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर होने वाला पलायन सामाजिक परिवर्तन की एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसने आगरा ज़िले के ग्रामीण समाज को गहराई से प्रभावित किया है। यह परिवर्तन एकतरफा न होकर द्वंद्वात्मक स्वरूप में प्रकट होता है, जिसमें कुछ सकारात्मक संभावनाएँ दिखाई देती हैं, वहीं अनेक गहरे और दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव भी उभर कर सामने आते हैं। आगरा ज़िले के ग्रामीण संदर्भ में यह द्वंद्व विशेष रूप से स्पष्ट रूप में परिलक्षित होता है।

पलायन का सबसे प्रमुख **सकारात्मक प्रभाव रेमिटेंस (Remittances)** के रूप में सामने आता है। शहरी क्षेत्रों में कार्यरत प्रवासी श्रमिकों द्वारा भेजी गई आय ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति को आंशिक रूप से सुदृढ़ करती है। इस आय से परिवारों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा आवास सुधार जैसे क्षेत्रों में व्यय संभव हो पाता है।

### तालिका 10: रेमिटेंस के प्रमुख सकारात्मक प्रभाव

| क्षेत्र | प्रभाव |
|---|---|
| पारिवारिक आय | आंशिक वृद्धि |
| बच्चों की शिक्षा | स्कूल नामांकन में वृद्धि |
| स्वास्थ्य | उपचार की बेहतर पहुँच |
| उपभोग स्तर | सुधार |

*स्रोत: Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI), Government of India.*
***Yogendra Singh (1977)****Modernization of Indian Tradition, Rawat Publications.*

तालिका 10 से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण पलायन से प्राप्त **रेमिटेंस (शहरी क्षेत्रों से भेजी गई आय)** आगरा ज़िले के ग्रामीण परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर कुछ **सकारात्मक प्रभाव** अवश्य डालती है। प्रवासी सदस्यों द्वारा भेजी गई आय से **पारिवारिक आय में आंशिक वृद्धि** होती है, जिससे परिवार दैनिक आवश्यकताओं, ऋण चुकौती और आकस्मिक खर्चों को बेहतर ढंग से संभाल पाते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव **बच्चों की शिक्षा** पर भी दिखाई देता है, जहाँ स्कूल में नामांकन बढ़ता है, निजी विद्यालयों की ओर झुकाव होता है और शिक्षा पर होने वाला व्यय बढ़ता है। इसी प्रकार रेमिटेंस के कारण परिवारों की **स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच** में सुधार होता है, क्योंकि वे सरकारी सेवाओं के साथ-साथ निजी उपचार, दवाइयों और अस्पताल सुविधाओं का भी उपयोग कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू उपकरणों, बेहतर भोजन, आवास सुधार और उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद के माध्यम से **उपभोग स्तर में सुधार** देखा जाता है। हालाँकि यह सुधार प्रायः अल्पकालिक और उपभोग-केंद्रित होता है, फिर भी यह ग्रामीण परिवारों के जीवन-स्तर में आंशिक उन्नयन को दर्शाता है। इस प्रकार तालिका यह संकेत देती है कि रेमिटेंस ग्रामीण परिवारों के लिए आर्थिक संबल का कार्य करती है, यद्यपि यह संरचनात्मक गरीबी का स्थायी समाधान नहीं बन पाती।

### तालिका 11: पलायन के नकारात्मक सामाजिक प्रभाव

| आयाम | प्रभाव |
|---|---|
| पारिवारिक संबंध | कमजोर |
| सामुदायिक एकजुटता | घटती |
| सामाजिक नियंत्रण | सीमित |
| सांस्कृतिक निरंतरता | बाधित |

*स्रोत:* **Desai,S.&Dubey,A.(2012)** Caste in 21st Century India: Competing Narratives, Economic and Political Weekly.

तालिका 11 यह दर्शाती है कि ग्रामीण-शहरी पलायन का प्रभाव केवल आर्थिक स्तर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसके **गहरे नकारात्मक सामाजिक परिणाम** भी दिखाई देते हैं। पलायन के कारण जब परिवार का कोई सदस्य (विशेषकर युवा या कमाऊ पुरुष) लंबे समय तक घर से बाहर रहता है, तो **पारिवारिक संबंध कमजोर** होने लगते हैं। पति-पत्नी के बीच भावनात्मक दूरी, बच्चों की देखभाल में कमी तथा बुज़ुर्गों की उपेक्षा जैसी समस्याएँ उभरती

हैं। इसी क्रम में गाँव स्तर पर **सामुदायिक एकजुटता घटती** है, क्योंकि पारंपरिक सहयोग, सामूहिक श्रम और सामाजिक सहभागिता में प्रवासी परिवारों की भूमिका कम हो जाती है।

इसके अतिरिक्त, पलायन से **सामाजिक नियंत्रण सीमित** हो जाता है। परंपरागत पंचायत, जातीय परिषदें और अनौपचारिक सामाजिक निगरानी तंत्र कमजोर पड़ते हैं, जिससे अनुशासन, नैतिकता और सामुदायिक उत्तरदायित्व में गिरावट आती है। साथ ही, प्रवासियों और उनके परिवारों के शहरी प्रभावों के कारण **सांस्कृतिक निरंतरता बाधित** होती है—लोक परंपराएँ, त्योहारों की सामूहिकता, पारंपरिक मूल्य और ग्रामीण जीवन शैली धीरे-धीरे क्षीण होने लगती है। इस प्रकार तालिका 11 यह स्पष्ट करती है कि पलायन ग्रामीण समाज की सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक स्थिरता के लिए एक गंभीर चुनौती के रूप में उभरता है।

तालिका 12: सामाजिक परिवर्तन के द्वंद्वात्मक स्वरूप

| **सकारात्मक आयाम** | **नकारात्मक आयाम** |
|---|---|
| आय में वृद्धि | सामाजिक विघटन |
| शिक्षा में जागरूकता | सांस्कृतिक दूरी |
| आधुनिक दृष्टिकोण | परंपरागत मूल्यों का क्षरण |
| जीवन-स्तर में सुधार | व्यक्तिवाद की वृद्धि |

*स्रोत:* **Anthony Giddens (1991)** *Modernity and Self-Identity*, Polity Press.

तालिका 12 सामाजिक परिवर्तन के **द्वंद्वात्मक (Dialectical) स्वरूप** को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करती है, जिसमें एक ही प्रक्रिया के अंतर्गत सकारात्मक और नकारात्मक—दोनों प्रकार के प्रभाव एक साथ दिखाई देते हैं। आय में वृद्धि जैसे सकारात्मक आयाम ने ग्रामीण परिवारों की आर्थिक क्षमता को सुदृढ़ किया है, जिससे उपभोग, स्वास्थ्य सेवाओं और बच्चों की शिक्षा पर अधिक व्यय संभव हुआ है। इसी के साथ शिक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता ने नई सोच, कौशल और अवसरों के द्वार खोले हैं तथा आधुनिक दृष्टिकोण के माध्यम से जाति, लिंग और पेशे से जुड़ी पारंपरिक जड़ताओं को आंशिक रूप से चुनौती मिली है। परिणामस्वरूप जीवन-स्तर में सुधार हुआ है और भौतिक सुविधाओं तक पहुँच बढ़ी है।

किन्तु इन्हीं सकारात्मक परिवर्तनों के समानांतर कुछ **गंभीर नकारात्मक आयाम** भी उभरकर सामने आए हैं। आय में वृद्धि और शहरी संपर्कों के कारण ग्रामीण समाज में **सामाजिक विघटन** की प्रवृत्ति बढ़ी है, जहाँ पारिवारिक और सामुदायिक बंधन कमजोर पड़ते जा रहे हैं। शिक्षा और आधुनिक जीवन शैली के प्रभाव से **सांस्कृतिक दूरी** उत्पन्न हुई है, जिसके परिणामस्वरूप नई पीढ़ी और पारंपरिक ग्रामीण संस्कृति के बीच अंतर गहराता जा रहा है। आधुनिक दृष्टिकोण के साथ **परंपरागत मूल्यों का क्षरण** देखने को मिलता है, जिससे सामूहिकता, सहयोग और नैतिक उत्तरदायित्व जैसी अवधारणाएँ प्रभावित होती हैं। इसके अतिरिक्त, जीवन-स्तर में सुधार ने **व्यक्तिवाद की वृद्धि** को भी प्रोत्साहित किया है, जो सामुदायिक सहभागिता और सामाजिक एकजुटता के लिए चुनौती बनता जा रहा है। इस प्रकार तालिका 12 यह रेखांकित करती है कि सामाजिक परिवर्तन न तो पूर्णतः लाभकारी है और न ही पूर्णतः हानिकारक, बल्कि यह एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है जिसमें लाभ और हानि साथ-साथ विद्यमान रहते हैं।

## निष्कर्ष

प्रस्तुत समाजशास्त्रीय अध्ययन से यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि आगरा जनपद में ग्रामीण रोजगार के अभाव ने पलायन को केवल एक आर्थिक विकल्प नहीं, बल्कि सामाजिक विवशता के रूप में स्थापित कर दिया है। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, सीमित गैर-कृषि रोजगार अवसर, भूमि का विखंडन और आजीविका की अस्थिरता ने ग्रामीण युवाओं को शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन के लिए बाध्य किया है। इस प्रक्रिया ने ग्रामीण समाज की पारंपरिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया है और परिवार तथा समुदाय दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न किए हैं।

पलायन के परिणामस्वरूप ग्रामीण परिवारों की संरचना में स्पष्ट परिवर्तन देखा गया है। कार्यशील पुरुषों के बाहर चले जाने से महिलाओं और बुजुर्गों पर आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक जिम्मेदारियों का भार बढ़ा है। महिलाओं की भूमिका घरेलू दायरे से आगे बढ़कर कृषि कार्यों और निर्णय-निर्माण तक विस्तृत हुई है, जिससे एक ओर सीमित स्तर पर सशक्तिकरण की प्रक्रिया दिखाई देती है, वहीं दूसरी ओर कार्यभार और मानसिक दबाव में वृद्धि भी हुई है। बच्चों की शिक्षा, सामाजिककरण और पारिवारिक देखरेख भी इस पलायन प्रक्रिया से प्रभावित हुई है। लंबे समय तक पारिवारिक अलगाव ने भावनात्मक दूरी, पारिवारिक संबंधों में शिथिलता और कभी-कभी पारिवारिक विघटन जैसी स्थितियों को जन्म दिया है।

सामुदायिक स्तर पर पलायन ने ग्रामीण सामाजिक संरचना को कमजोर किया है। गाँवों में युवाओं की कमी से सामुदायिक सहभागिता, सामूहिक श्रम, पारंपरिक संस्थाओं और सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रियाएँ प्रभावित हुई हैं। पंचायत, जाति-आधारित सहयोग और सामूहिक सांस्कृतिक गतिविधियों की भूमिका धीरे-धीरे सीमित होती जा रही है। इसके स्थान पर व्यक्तिवाद, सामाजिक दूरी और असमान सहभागिता की प्रवृत्ति उभर रही है। ग्रामीण समुदायों में वृद्ध जनसंख्या का अनुपात बढ़ने से सामाजिक गतिशीलता और नवाचार की क्षमता भी प्रभावित हुई है।

यद्यपि पलायन के कुछ सकारात्मक पहलू भी सामने आते हैं, जैसे प्रवासी श्रमिकों द्वारा भेजी गई आय से कुछ परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार और शिक्षा-स्वास्थ्य पर बढ़ता व्यय, तथापि इसके नकारात्मक सामाजिक प्रभाव अधिक गहरे और दीर्घकालिक हैं। सांस्कृतिक दूरी, पारंपरिक मूल्यों का क्षरण और सामाजिक एकजुटता में कमी ग्रामीण समाज की स्थिरता के लिए चुनौती बनकर उभरी है।

अतः यह अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि आगरा जनपद में ग्रामीण रोजगार का अभाव और उससे उत्पन्न पलायन केवल आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक प्रश्न है। इसके समाधान के लिए ग्रामीण विकास नीतियों में रोजगार सृजन के साथ-साथ परिवार और समुदाय के सामाजिक आयामों को भी केंद्रीय महत्व देना आवश्यक है। स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार, कौशल विकास, गैर-कृषि गतिविधियों का विस्तार और सामाजिक सुरक्षा की प्रभावी व्यवस्था ही ग्रामीण समाज में संतुलन, स्थिरता और सतत विकास सुनिश्चित कर सकती है।

**संदर्भ सूची :**

1. **श्रीनिवास, एम. एन. (1966).** *आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन* नई दिल्ली: ओरिएंट लॉन्गमैन।
2. **योगेन्द्र सिंह (1977).** *भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण* जयपुर: रावत पब्लिकेशन्स।
3. **देसाई, ए. आर. (2005).** *भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र* मुंबई: पॉपुलर प्रकाशन।
4. **गिडेन्स, एंथनी (1991).** *आधुनिकता और आत्म-पहचान* कैम्ब्रिज: पॉलिटी प्रेस।
5. **टोडारो, माइकल पी. (1969).** "श्रम पलायन एवं शहरी बेरोज़गारी का मॉडल" *अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू,* खंड 59 (1)।
6. **भारत की जनगणना (2011).** *उत्तर प्रदेश में पलायन एवं सामाजिक-आर्थिक विशेषताएँ* भारत सरकार, रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय।
7. **राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय – NSSO (2007–08).** *भारत में पलायन (64 वाँ दौर)* सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।
8. **कुमार, बी. बी. (2012).** *भारत में ग्रामीण विकास: समस्याएँ और चुनौतियाँ* नई दिल्ली: अनमोल पब्लिकेशन्स।
9. **सिंह, के. एस. (1998).** *भारत के लोग: सामाजिक एवं सांस्कृतिक निरंतरता और परिवर्तन* नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
10. **आहूजा, राम (2010).** *भारतीय समाज* जयपुर: रावत पब्लिकेशन्स।